

एनसीडब्ल्यू के दायरे का वसितार

प्रलिस के लयि:

महलाओं के कल्याण के लयि कानूनी ढाँचा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पृष्ठभूमि और जनादेश ।

मेन्स के लयि:

देश में महलाओं की बढ़ती ज़रूरतें, राष्ट्रीय महिला आयोग की पृष्ठभूमि और जनादेश ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW) का 30वाँ स्थापना दविस (31 जनवरी) मनाया गया ।

- प्रधानमंत्री के मुताबकि, देश में महलाओं की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए एनसीडब्ल्यू का दायरा बढ़ाया जाना चाहयि ।

प्रमुख बदि

राष्ट्रीय महिला आयोग के दायरे का वसितार करने की आवश्यकता:

- नए भारत का विकास:
 - [आत्मनिर्भर भारत \(Atmanirbhar Bharat\)](#) अभयान ने देश के विकास और महलाओं की क्षमता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कयि है ।
 - यह परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि [प्रधानमंत्री मुद्रा योजना \(Pradhan Mantri MUDRA Yojana\)](#) में लगभग 70% महिला लाभार्थी शामिल हैं ।
 - देश में पछिले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या में तीन गुना वृद्धि देखी गई है ।
 - इसी तरह वर्ष 2016 के बाद उभरे 60 हजार से ज्यादा [सर्टिफाइड एम्प्लॉयमेंट सेन्टर](#) में से 45 फीसदी में कम-से-कम एक महिला नदिशक शामिल है ।
- समाज में पुरानी सोच:
 - कपड़ा से लेकर डेयरी उद्योग महलाओं के कौशल और शक्ति के कारण आगे बढ़े हैं ।
 - भारत की अर्थव्यवस्था [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों](#) पर निर्भर है, ऐसे में देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।
 - हालाँकि यह खेदजनक है कि पुरानी सोच वाले लोगों के वचार से महलाओं की भूमिकाएँ केवल घरेलू काम तक ही सीमति हैं ।
- महलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध:
 - NCW ने सूचति कयि कि पछिले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2021 के पहले आठ महीनों में महलाओं के खिलाफ अपराधों की शकियतों में 46% की वृद्धि हुई थी ।
 - महलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों में [घरेलू हिंसा, ववाहित महलाओं का उत्पीड़न](#) या दहेज उत्पीड़न, [कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार तथा बलात्कार का प्रयास](#) और [साइबर अपराध](#) शामिल हैं ।

NCW की पृष्ठभूमि और जनादेश:

- पृष्ठभूमि:
 - भारत में महलाओं की स्थितिपर गठति समिति (CSWI) ने लगभग पाँच दशक पहले शकियतों के नविरण की सुवधि एवं महलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में तीव्रता लाने हेतु नगिरानी कार्यों को पूरा करने के लयि 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की स्थापना की सफारशि की थी ।
 - महलाओं के लयि राष्ट्रीय परिरेक्ष्य योजना (1988-2000) सहति अन्य सभी समतियों और आयोगों ने महलाओं के लयि एक शीर्ष

निकाय के गठन की सफ़ारिश की।

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
- आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को 'जयंती पटनायक' की अध्यक्षता में किया गया था।
 - आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पांच अन्य सदस्य होते हैं। NCW के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

■ जनादेश और कार्य:

- इसका प्राथमिक उद्देश्य उपयुक्त नीति निर्माण और वधायी उपायों के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम बनाना और जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता एवं समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना है।
- इसके कार्यों में शामिल हैं:
 - महिलाओं के लिये संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
 - उपचारात्मक वधायी उपायों की सफ़ारिश करना।
 - शक़ायतों के नविवरण को सुगम बनाना।
 - महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतित्मक मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- इसने बड़ी संख्या में शक़ायतें प्राप्त की हैं और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिये कई मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है।
- इसने बाल विवाह, प्रायोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों के मुद्दे को उठाया और कानूनों की समीक्षा की, जैसे:
 - [दहेज नषिध अधिनियम, 1961](#)
 - [गरभधारण पूर्व और परसव पूर्व नदिन तकनीक अधिनियम 1994](#)
 - [भारतीय दंड संहति 1860](#)

महिलाओं के कल्याण हेतु प्रमुख कानूनी ढाँचा:

■ संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- [मौलिक अधिकार](#):
 - यह सभी भारतीयों को समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 15[1]) और महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा किये जाने वाले विशेष प्रावधानों (अनुच्छेद 15[3]) की गारंटी देता है।
- [मौलिक करतव्य](#):
 - अनुच्छेद 51(A) के तहत महिलाओं की गरमा को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित अपमानजनक प्रथाओं को प्रतर्बिधति किया गया है।

■ वधायी ढाँचा:

- [घरेलू हसिा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005](#)
- [दहेज नषिध अधिनियम, 1961](#)
- [कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन \(रोकथाम, नषिध और नविवरण\) अधिनियम, 2013](#)
- [बाल यौन अपराध संरक्षण \(POCSO\), 2012](#)

■ महिलाओं से संबंधित योजनाएँ:

- [बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना](#)।
- [वन स्टॉप सेंटर योजना](#)।
- [उज्ज्वला योजना](#)।
- [स्वाधार गृह](#) (कठनि परस्थितियों में महिलाओं के लिये एक योजना)।
- नारी शक़ता पुरस्कार।
- महिला पुलसि स्वयंसेवक।
- महिला शक़ता केंद्र ([MSK](#))।
- [नरिभया](#)।

आगे की राह

- NCW अधिनियम में संशोधन: वर्तमान भारत में महिलाओं की भूमिका में लगातार वृद्धि हो रही है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की भूमिका का वसितार समय की आवश्यकता है।
 - इस संदर्भ में [राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990](#) को अधिक कठोर और प्रभावी बनाने के लिये इसमें संशोधन किया जाना चाहिये।
 - इसके अलावा राज्य आयोगों को भी अपने दायरे का वसितार करना चाहिये।
- [विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना: बेटियों की शादी की उमर को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कम उमर में शादी बेटियों की शक़िषा व करियर में बाधा न बने।](#)
- [महिलाओं के खिलाफ हसिा को संबोधित करना:](#) महिलाओं के खिलाफ होने वाली हसिा समानता, विकास, शांति के साथ-साथ महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की पूर्ता में एक बाधा बनी हुई है।
 - कुल मलिकर [सतत विकास लक्ष्यों \(SDGs\)](#) का वादा- 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना', महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हसिा को समाप्त किये बिना पूरा नहीं किया जा सकता है।

- समग्र प्रयास: महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का समाधान केवल कानून के तहत अदालतों में ही नहीं किया जा सकता है बल्कि इसके लिये एक समग्र दृष्टिकोण और पूरे पारस्थितिकी तंत्र को बदलना आवश्यक है।
 - इसके लिये कानून निर्माताओं, पुलिस अधिकारियों, फॉरेंसिक विभाग, अभियोजकों, न्यायपालिका, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, गैर-सरकारी संगठनों, पुनर्वास केंद्रों सहित सभी हतिधारकों को एक साथ मलिकर कार्य करने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/expanding-scope-of-ncw>

